

I
A
S



P
C
S

Committed To Excellence

DAILY

CURRENT AFFAIRS ANALYSIS

(Pre+Mains) with MCQ



NATIONAL & INTERNATIONAL



POLITY & GOVERNANCE



ECONOMY



DEVELOPMENT & SCIENCE



ENVIRONMENT & ECOLOGY



DEFENCE & SECURITY



15 JUNE 2026



FOR PDF DOWNLOAD
GS WORLD LEARNING APP



1. भारत का पहला स्वदेशी AI वीडियो मॉडल 'Varya' लॉन्च

भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला स्वदेशी Distilled Video Story-Generating AI Model 'Varya' लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा प्रस्तुत यह मॉडल भारत में जनरेटिव AI तकनीक को अधिक सुलभ, किफायती और भारतीय जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

क्या है Varya AI Model?

- Varya एक उन्नत Foundation AI Video Model है, जिसे AI-आधारित कंपनी Avataar ने विकसित किया है। यह Text-to-Video और Image-to-Video तकनीक पर कार्य करता है।
- उपयोगकर्ता केवल एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या तस्वीर अपलोड करके उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त निर्देश देकर इन वीडियो को लंबी डिजिटल कहानियों में भी परिवर्तित किया जा सकता है।

Distillation Technology से बढ़ी गति और दक्षता

- Varya की सबसे बड़ी विशेषता इसकी Distillation Technology है। यह तकनीक बड़े और जटिल AI मॉडल को छोटे तथा अधिक कुशल मॉडल में परिवर्तित करती है।
- जहां पारंपरिक AI वीडियो मॉडल को वीडियो तैयार करने के लिए लगभग 50 चरणों की आवश्यकता होती है, वहीं Varya केवल 4 चरणों में ही उच्च गुणवत्ता वाला वीडियो तैयार कर सकता है।

बेहद कम लागत में वीडियो निर्माण

- विशेषज्ञों के अनुसार, Varya के माध्यम से वीडियो निर्माण की लागत लगभग 48 पैसे प्रति सेकंड है।
- यह लागत वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कई AI वीडियो मॉडलों की तुलना में काफी कम है।
- इससे छात्रों, शिक्षकों, स्टार्टअप्स, डिजिटल मार्केटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को कम खर्च में आधुनिक AI तकनीक का लाभ मिल सकेगा।

भारतीय संस्कृति और भाषाओं की बेहतर समझ

- Varya को भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों पर प्रशिक्षित किया गया है।
- इसके कारण यह विभिन्न भारतीय त्योहारों, क्षेत्रीय परिधानों, खान-पान, भाषाओं और स्थानीय जीवनशैली को अधिक सटीकता से प्रस्तुत करने में सक्षम है।
- यह विशेषता इसे भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक उपयोगी बनाती है।

MSMEs के लिए नया अवसर

- विशेषज्ञों का मानना है कि Varya छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
- इसके माध्यम से व्यवसाय अपनी स्थानीय भाषा में कम लागत वाले विज्ञापन, प्रचार वीडियो और डिजिटल मार्केटिंग सामग्री तैयार कर सकेंगे, जिससे उनकी बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।

डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम

- Varya का लॉन्च भारत के स्वदेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

- यह पहल न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत को वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी सहायक होगी।

2. DRDO के स्वदेशी 'नेत्र' AEW&C सिस्टम को मिली Final Operational Clearance

भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित **Netra Airborne Early Warning and Control (AEW&C) System** को Final Operational Clearance (FOC) प्रदान कर दी गई है। इस उपलब्धि के साथ भारतीय वायुसेना (IAF) की हवाई निगरानी, कमांड एवं कंट्रोल तथा युद्ध प्रबंधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

क्या है Netra AEW&C सिस्टम?

- 'नेत्र' भारत का पहला स्वदेशी Airborne Early Warning and Control (AEW&C) प्लेटफॉर्म है। इसे भारतीय वायुसेना की "Eye in the Sky" यानी "आसमान में आंख" कहा जाता है। यह एक उड़ता हुआ रडार स्टेशन है, जो पारंपरिक जमीनी रडारों की सीमा से कहीं अधिक दूर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी कर सकता है।
- इस प्रणाली का विकास DRDO ने देश में स्वदेशी हवाई निगरानी अवसंरचना विकसित करने और भारतीय वायुसेना को एक प्रभावी Force Multiplier उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया है।

कैसे करता है काम?

- नेत्र प्रणाली 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विशाल हवाई क्षेत्र की निगरानी करती है। विमान के ऊपर लगे अत्याधुनिक रडार द्वारा लगातार इलेक्ट्रॉनिक संकेत प्रसारित किए जाते हैं, जिससे पहाड़ों और अन्य भौगोलिक बाधाओं के कारण छिपे लक्ष्यों का भी पता लगाया जा सकता है।
- ऑनबोर्ड कंप्यूटर प्राप्त संकेतों का विश्लेषण कर मित्र और शत्रु विमानों की पहचान करते हैं। इसके बाद सुरक्षित और Jam-Resistant Data Links के माध्यम से यह जानकारी वास्तविक समय में लड़ाकू विमानों और जमीनी कमांड केंद्रों तक पहुंचाई जाती है।

200 से अधिक लक्ष्यों पर एक साथ नजर

- नेत्र प्लेटफॉर्म में अत्याधुनिक **Active Electronically Scanned Array (AESA) Radar** लगाया गया है।
- यह लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी करने में सक्षम है तथा एक साथ 200 से अधिक हवाई लक्ष्यों—जिनमें लड़ाकू विमान, मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं—को ट्रैक कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी सक्षम

- नेत्र केवल हवाई लक्ष्यों की निगरानी तक सीमित नहीं है। इसमें Electronic Support Measures (ESM) और Communication Support Measures (CSM) जैसी उन्नत प्रणालियां भी शामिल हैं, जो दुश्मन के रडार नेटवर्क, संचार प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम हैं।
- इसके अतिरिक्त, इसमें Self-Protection Electronic Warfare Suite भी मौजूद है, जो दुश्मन की मिसाइलों को भ्रमित कर विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

ब्राजीलियाई विमान पर आधारित स्वदेशी प्रणाली

- नेत्र प्रणाली को ब्राजील के Embraer EMB-145 विमान प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। इस विमान में विशेष रडार, अतिरिक्त विद्युत उत्पादन प्रणाली, इन-फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब तथा उन्नत कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि मिशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निर्बाध ऊर्जा और शीतलन मिल सके।

भारत की वायु रक्षा को मिलेगा नया बल

- विशेषज्ञों के अनुसार, नेत्र AEW&C सिस्टम भारतीय वायुसेना की नेटवर्क-सेंट्रिक युद्ध क्षमता को मजबूत करेगा। यह भारत के IL-76 आधारित Phalcon AWACS सिस्टम के साथ मिलकर बहु-स्तरीय हवाई निगरानी और वायु रक्षा कवच तैयार करेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ की निगरानी, दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने तथा लड़ाकू विमानों के संचालन में यह प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि

- नेत्र को Final Operational Clearance मिलना भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह न केवल देश की स्वदेशी तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करता है, बल्कि भविष्य में उन्नत हवाई निगरानी प्रणालियों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

3. जापान के H3 रॉकेट की सफल उड़ान, पिछली विफलता के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिली बड़ी राहत

जापान के प्रमुख H3 रॉकेट ने हाल ही में तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक उड़ान भरते हुए देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि दिसंबर में हुए पिछले मिशन के दौरान दूसरे चरण के इंजन के समय से पहले बंद हो जाने के कारण मिशन विफल हो गया था।

- इस सफल प्रक्षेपण के साथ जापान ने अपनी अगली पीढ़ी की लॉन्च प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रदर्शित किया है और वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

क्या है H3 रॉकेट?

- H3 जापान का अगली पीढ़ी का फ्लैगशिप लॉन्च व्हीकल है, जिसे पुराने H-IIA रॉकेट की जगह लेने के लिए विकसित किया गया है। यह एक तरल-ईंधन (Liquid Propellant) आधारित भारी-भार वहन करने वाला रॉकेट है, जिसे अधिक विश्वसनीय, लचीला और कम लागत वाला बनाया गया है।
- इसका विकास **Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)** और **Mitsubishi Heavy Industries (MHI)** ने संयुक्त रूप से किया है।

लॉन्च लागत में लगभग 50% की कमी

- H3 रॉकेट की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लागत-प्रभावशीलता है। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि H-IIA रॉकेट की तुलना में प्रक्षेपण लागत लगभग 50 प्रतिशत तक कम हो सके।
- इसके लिए व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ऑटोमोबाइल पुर्जों तथा 3D-प्रिंटेड हार्डवेयर का उपयोग किया गया है, जिससे उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई है।

अत्याधुनिक LE-9 इंजन से लैस

- रॉकेट के प्रथम चरण में नया **LE-9 इंजन** लगाया गया है, जो उन्नत Expander Bleed Cycle तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक प्रक्षेपण के दौरान अधिक सुरक्षा, बेहतर ईंधन दक्षता और उच्च थ्रस्ट प्रदान करती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, LE-9 इंजन जापान की अंतरिक्ष प्रणोदन तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।

चंद्र मिशनों और बड़े उपग्रहों के लिए तैयार

- H3 रॉकेट को बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रहों, सैन्य उपग्रहों तथा भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी भारी पेलोड क्षमता भविष्य में चंद्रमा पर स्थापित किए जाने वाले संभावित आधारों तक भारी उपकरण और सामग्री पहुंचाने में भी उपयोगी हो सकती है।

मॉड्यूलर डिजाइन से बढ़ी लचीलापन क्षमता

- H3 की संरचना मॉड्यूलर है, जिससे विभिन्न मिशनों की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें 0, 2 या 4 ठोस रॉकेट बूस्टर लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न आकार के पेलोड फेयरिंग का उपयोग कर इसे अलग-अलग कक्षीय मिशनों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में जापान की नई चुनौती

- H3 रॉकेट को वैश्विक लॉन्च बाजार में SpaceX के Falcon 9, भारत के LVM3, यूरोप के Ariane 6 और चीन के Long March 5 जैसे प्रमुख रॉकेटों का प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि कम लागत और उच्च विश्वसनीयता के कारण H3 आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में जापान की हिस्सेदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

- H3 की सफलता जापान की स्वतंत्र अंतरिक्ष पहुंच (Autonomous Space Access) सुनिश्चित करने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उपलब्धि न केवल जापान की तकनीकी क्षमता को मजबूत करती है, बल्कि देश को भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्यिक मिशनों के लिए भी नई संभावनाएं प्रदान करती है।

4. AI डेटा सेंटरों पर बढ़ता पर्यावरणीय विरोध, दुनिया भर में तेज हुई बहस

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तेजी से विस्तार के साथ दुनिया भर में विशाल AI डेटा सेंटरों के निर्माण की होड़ तेज हो गई है। हालांकि, इन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया सहित कई क्षेत्रों में विरोध भी बढ़ता जा रहा है। स्थानीय समुदायों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि AI डेटा सेंटर ऊर्जा, जल और भूमि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रहे हैं, जिससे पर्यावरण और स्थानीय आबादी दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

क्या हैं AI डेटा सेंटर?

- AI डेटा सेंटर विशाल हाइपर-स्केल कंप्यूटिंग सुविधाएं हैं, जिन्हें जटिल मशीन लर्निंग और जनरेटिव AI मॉडल को प्रशिक्षित करने तथा संचालित करने के लिए बनाया जाता है।
- पारंपरिक डेटा सेंटर मुख्यतः डिजिटल सूचनाओं के भंडारण का कार्य करते हैं, जबकि AI डेटा सेंटरों को अरबों गणनाएं प्रति सेकंड करने के लिए लगातार उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है।
- इन्हें आधुनिक युग के "सुपरकंप्यूटर परिसरों" के रूप में देखा जा रहा है, जो AI आधारित सेवाओं की रीढ़ बन चुके हैं।

वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा विरोध

- रिपोर्टों के अनुसार, केवल वर्ष 2025 में अमेरिका में स्थानीय विरोध और जन आंदोलनों के कारण लगभग 152 अरब डॉलर मूल्य की डेटा सेंटर परियोजनाएं विलंबित या अवरुद्ध हुईं।
- कई समुदायों का मानना है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय जल संसाधनों और बिजली नेटवर्क पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है।

- यूरोप में भी कई बड़े डेटा सेंटर प्रस्तावों को रद्द या पुनर्विचार के लिए रोक दिया गया है। कई देशों ने छोटे, क्षेत्रीय और हरित ऊर्जा आधारित डेटा हब को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है।

भारत में AI अवसंरचना विस्तार की तैयारी

- भारत भी AI डेटा सेंटरों का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में Adani Group ने वर्ष 2035 तक 100 अरब डॉलर के निवेश के साथ 5 गीगावाट AI अवसंरचना प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना की घोषणा की है।
- इसके अलावा Google और Adani Group की साझेदारी में विशाखापत्तनम में 2 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर विकसित किया जा रहा है, जिसे देश का सबसे बड़ा हाइपर-स्केल डेटा सेंटर माना जा रहा है।
- इस परियोजना के लिए लगभग 480 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जो पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील तटीय क्षेत्र में स्थित है।

जल और बिजली संसाधनों पर बढ़ता दबाव

- विशेषज्ञों का कहना है कि AI डेटा सेंटरों की सबसे बड़ी चुनौती उनकी अत्यधिक ऊर्जा और जल खपत है। हजारों सर्वरों को ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में पानी और निरंतर बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुछ बड़ी तकनीकी परियोजनाओं को 15 वर्षों तक बिजली और 10 वर्षों तक जल सब्सिडी प्रदान किए जाने के फैसले ने भी संसाधन वितरण को लेकर बहस को जन्म दिया है।
- आलोचकों का तर्क है कि इससे स्थानीय समुदायों पर संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर बढ़ी चिंता

- पर्यावरणविदों के अनुसार, तटीय क्षेत्रों, कृषि भूमि और बागानों में बड़े डेटा सेंटर स्थापित करने से भूमि क्षरण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और भूजल संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- इसके अतिरिक्त, कई परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA) से छूट दिए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय जोखिमों का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता।

वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण में अंतर

- जहां यूरोपीय संघ और अमेरिका में डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए कठोर पर्यावरणीय मूल्यांकन और संसाधन प्रभाव अध्ययन अनिवार्य किए जा रहे हैं, वहीं भारत में कर छूट, भूमि रियायतें तथा जल और बिजली सब्सिडी जैसी प्रोत्साहन नीतियों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि AI क्षेत्र में निवेश आवश्यक है, लेकिन पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधन संरक्षण को समान महत्व देना भी उतना ही जरूरी है।

संतुलित विकास की आवश्यकता

- विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि बड़े डेटा सेंटरों के लिए अनिवार्य पर्यावरण प्रभाव आकलन, जल पुनर्चक्रण प्रणाली, उन्नत कूलिंग तकनीक तथा बाजार आधारित बिजली एवं जल मूल्य निर्धारण जैसी नीतियां अपनाई जानी चाहिए।
- इसके साथ ही, बड़े तटीय हाइपर-स्केल केंद्रों के बजाय छोटे क्षेत्रीय और हरित ऊर्जा आधारित डेटा हब विकसित करने पर भी विचार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

- AI क्रांति वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास को नई दिशा दे रही है, लेकिन इसके लिए आवश्यक डेटा सेंटरों की पर्यावरणीय लागत भी लगातार सामने आ रही है। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह AI अवसंरचना के विस्तार और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सतत एवं जिम्मेदार तकनीकी विकास का मार्ग अपनाए।

5. भारत-फ्रांस ATL ब्रिज की स्थापना, नवाचार और शिक्षा सहयोग को मिलेगा नया आयाम

भारत और फ्रांस के बीच शिक्षा, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से **India-France ATL Bridge** की आधिकारिक स्थापना की गई है। यह पहल फ्रांस के नीस शहर में आयोजित **Bharat Innovates 2026 Summit** के दौरान शुरू की गई। इसे दोनों देशों के बीच नवाचार-आधारित साझेदारी को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

- यह पहल भारत के **Atal Innovation Mission (AIM)**, **NITI Aayog** और फ्रांस की **La Fondation Dassault Systèmes** के संयुक्त सहयोग से स्थापित की गई है।

क्या है India-France ATL Bridge?

- India-France ATL Bridge एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहयोग मंच है। इसका उद्देश्य भारत और फ्रांस के छात्रों, शिक्षकों तथा नवाचार संस्थानों को एक साझा मंच पर जोड़ना है।
- यह पहल स्कूल स्तर पर वैज्ञानिक सोच, इंजीनियरिंग कौशल और डिज़ाइन थिंकिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ दोनों देशों के युवा नवाचारकर्ताओं को वैश्विक समस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए सहयोग का अवसर प्रदान करेगी।

फ्रांस में स्थापित होगी पहली ATL आधारित इनोवेशन लैब

- इस पहल के अंतर्गत फ्रांस में पहली बार भारत के **Atal Tinkering Lab (ATL)** मॉडल पर आधारित **School Innovation Lab** स्थापित की जाएगी।
- यह प्रयोगशाला छात्रों को रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), 3D प्रिंटिंग, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और डिज़ाइन थिंकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगी।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी।

छात्रों और उद्यमियों के लिए वैश्विक अवसर

- ATL Bridge के माध्यम से छात्र विनिमय कार्यक्रम, मेंटरशिप नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय नवाचार परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इससे भारत और फ्रांस के युवा नवाचारकर्ताओं को वैश्विक विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, यह मंच उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को भी प्रोत्साहित करेगा।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना से प्रेरित पहल

- इस पहल की वैचारिक आधारशिला भारत की प्राचीन अवधारणा **"वसुधैव कुटुम्बकम्"** है, जिसका अर्थ है "पूरा विश्व एक परिवार है"।
- इस सिद्धांत के अनुरूप दोनों देश शिक्षा, नवाचार और तकनीकी ज्ञान को साझा कर वैश्विक विकास और मानव कल्याण के लिए सहयोग करेंगे।

Bharat Innovates 2026: वैश्विक मंच पर भारत की नवाचार शक्ति

क्या है Bharat Innovates 2026?

- Bharat Innovates 2026 एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय Deep-Tech Acceleration Programme है, जिसका उद्देश्य भारत की उभरती तकनीकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना है।
- यह कार्यक्रम भारतीय अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप्स और विश्वविद्यालयों को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, उद्योगों और तकनीकी भागीदारों से जोड़ने का कार्य करेगा।
- इस कार्यक्रम का आयोजन **भारत के शिक्षा मंत्रालय** के नेतृत्व में किया जा रहा है तथा वर्ष 2026 को **India-France Year of Innovation** के रूप में मनाया जा रहा है।

120 भारतीय Deep-Tech स्टार्टअप्स को मिलेगा वैश्विक मंच

- Bharat Innovates 2026 में भारत के लगभग 120 अग्रणी Deep-Tech स्टार्टअप्स भाग ले रहे हैं। उन्हें वैश्विक निवेशकों, खरीदारों और तकनीकी साझेदारों के साथ प्रत्यक्ष संवाद का अवसर मिलेगा।
- कार्यक्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और अन्य प्रमुख अनुसंधान संस्थान भी अपनी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

13 उभरते तकनीकी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है—

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
- सेमीकंडक्टर
- क्वांटम कंप्यूटिंग
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
- रक्षा तकनीक
- जैव प्रौद्योगिकी
- जलवायु तकनीक
- स्मार्ट मोबिलिटी
- उन्नत विनिर्माण

निवेश और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा

- Bharat Innovates 2026 में विशेष Investor-Innovator Matchmaking Platforms बनाए गए हैं, जहां स्टार्टअप्स और निवेशकों के बीच सीधा संवाद हो सकेगा।
- इसके अलावा, संयुक्त अनुसंधान (Joint R&D), सह-इन्क्यूबेशन (Co-incubation) और उत्पाद परीक्षण (Product Validation) जैसी व्यवस्थाएं भी विकसित की जा रही हैं, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने में सहायता मिलेगी।

भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया बल

- विशेषज्ञों का मानना है कि India–France ATL Bridge और Bharat Innovates 2026 दोनों पहलें शिक्षा, विज्ञान, नवाचार और स्टार्टअप सहयोग के क्षेत्र में भारत–फ्रांस संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।
- यह साझेदारी भविष्य की तकनीकों में संयुक्त नेतृत्व स्थापित करने और वैश्विक चुनौतियों के समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

6. BRICS देशों ने अपनाया 'इंदौर घोषणा पत्र', खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि पर बढ़ेगा सहयोग

भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए BRICS देशों ने जून 2026 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित कृषि मंत्रियों की बैठक में सर्वसम्मति से **BRICS Indore Declaration** को अपनाया। यह घोषणा पत्र कृषि, खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह घोषणा पत्र किसानों को नीति निर्माण के केंद्र में रखते हुए टिकाऊ कृषि, डिजिटल नवाचार और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक साझा रोडमैप प्रस्तुत करता है।

क्या है BRICS इंदौर घोषणा पत्र?

- BRICS इंदौर घोषणा पत्र एक संयुक्त कृषि चार्टर (Agricultural Charter) है, जिसे BRICS सदस्य देशों ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीकार किया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय और कल्याण को सुदृढ़ करना तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

कृषि पारिस्थितिकी और पुनर्योजी कृषि के लिए उत्कृष्टता केंद्र

- घोषणा पत्र के तहत **BRICS Network of Centres of Excellence on Agro-Ecology and Regenerative Agriculture** की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
- यह नेटवर्क प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, पुनर्योजी (Regenerative) कृषि और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देगा।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र अधिक सक्षम बन सकेगा।

डिजिटल कृषि में सहयोग बढ़ाने पर जोर

- घोषणा पत्र में **BRICS Network on Digital Agriculture** की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
- इस पहल के माध्यम से सदस्य देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी (Geospatial Technology), डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) और डेटा आधारित कृषि समाधान विकसित करने में सहयोग करेंगे।
- इसका उद्देश्य तकनीकी नवाचार के माध्यम से कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

किसानों के बीज अधिकारों की सुरक्षा

- BRICS देशों ने **Global Forum on Farmers' Rights in Seed Systems** स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
- इस मंच का उद्देश्य किसानों के पारंपरिक बीजों, स्वदेशी ज्ञान और जैव विविधता की रक्षा करना है। साथ ही, यह किसानों के बीज संसाधनों पर अधिकारों को मजबूत करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

AgriN नेटवर्क से बढ़ेगा कृषि अनुसंधान सहयोग

- घोषणा पत्र के अंतर्गत **BRICS AgriN (Agro Inputs, Genetic Resources and Information Network)** की स्थापना की जाएगी।

- यह नेटवर्क सदस्य देशों के बीच कृषि आदानों, आनुवंशिक संसाधनों, उन्नत बीज किस्मों और तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। इससे कृषि अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को नई गति मिलने की उम्मीद है।

खाद्य सुरक्षा के लिए साझा रणनीति

- विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चुनौतियों के बीच BRICS इंदौर घोषणा पत्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित रणनीति प्रदान करता है।
- यह घोषणा पत्र पर्याप्त, पौष्टिक और सुलभ खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में स्थिरता और समावेशी विकास को भी बढ़ावा देगा।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की पहल

- घोषणा पत्र में जलवायु-लचीली कृषि (Climate-Resilient Agriculture), टिकाऊ भूमि प्रबंधन, जल संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल कृषि तकनीकों पर विशेष बल दिया गया है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल BRICS देशों को कृषि क्षेत्र में हरित और टिकाऊ विकास मॉडल अपनाने में सहायता करेगी।

निष्कर्ष

BRICS इंदौर घोषणा पत्र कृषि, खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग का एक नया अध्याय खोलता है। डिजिटल कृषि, पुनर्योजी खेती, बीज अधिकारों की सुरक्षा और जलवायु-अनुकूल कृषि पर केंद्रित यह पहल भविष्य की खाद्य चुनौतियों से निपटने के लिए BRICS देशों को एक साझा मंच प्रदान करती है। यह घोषणा पत्र वैश्विक कृषि शासन में विकासशील देशों की भूमिका को भी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

7. झारखंड के चार पारंपरिक उत्पादों को मिला GI टैग, आदिवासी कला और शिल्प को मिली नई पहचान

झारखंड की समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्पकला को बड़ी पहचान मिली है। राज्य के चार पारंपरिक उत्पादों—**भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और झारखंड बांस शिल्प**—को आधिकारिक रूप से **भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication - GI) टैग** प्रदान किया गया है। इसे राज्य के कारीगरों, बुनकरों और आदिवासी समुदायों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि GI टैग मिलने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी तथा स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी।

क्या होता है GI टैग?

- भौगोलिक संकेतक (GI) टैग एक बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Right) है, जो उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिनकी विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशिष्ट पहचान किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है।
- भारत में GI टैग का पंजीकरण **Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999** के तहत किया जाता है।
- GI टैग उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और उनकी नकल या गलत उपयोग को रोकता है।

भगैया सिल्क और कुचाई सिल्क को मिली नई पहचान

- झारखंड के **भगैया सिल्क** और **कुचाई सिल्क** अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक, मजबूती और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन पद्धति के लिए प्रसिद्ध हैं।

- ये दोनों रेशम मुख्य रूप से जंगली टसर (Tussar) रेशम पर आधारित हैं और पारंपरिक हस्तचालित तकनीकों से तैयार किए जाते हैं। इनका उत्पादन झारखंड की समृद्ध हस्तकरघा परंपरा और स्थानीय कारीगरों की उत्कृष्ट कौशल का प्रतीक माना जाता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि GI टैग मिलने से झारखंड के टसर रेशम उद्योग को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी।

मुंडा ज्वेलरी: आदिवासी संस्कृति की अनमोल धरोहर

- मुंडा ज्वेलरी** झारखंड के मुंडा जनजातीय समुदाय की पारंपरिक धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- इन आभूषणों की विशेषता इनके ज्यामितीय डिज़ाइन, प्रकृति-प्रेरित आकृतियां और पारंपरिक हस्तनिर्माण तकनीक हैं। मुंडा समुदाय में इन आभूषणों का सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व भी है।
- GI टैग से इस पारंपरिक कला के संरक्षण और प्रचार को बढ़ावा मिलेगा।

झारखंड बांस शिल्प को भी मिला संरक्षण

- झारखंड का **बांस शिल्प** राज्य के ग्रामीण और वन क्षेत्रों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है।
- स्थानीय कारीगर बांस से टोकरियां, चटाइयां, घरेलू उपयोग की वस्तुएं तथा सजावटी उत्पाद तैयार करते हैं। यह शिल्प पर्यावरण-अनुकूल होने के साथ-साथ टिकाऊ विकास और हरित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, GI टैग मिलने से बांस आधारित उद्यमिता और ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

GI टैग से कारीगरों को होगा लाभ

- GI टैग मिलने के बाद इन उत्पादों की प्रामाणिकता प्रमाणित होगी और उनकी नकली प्रतियों पर रोक लगेगी। इससे स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा तथा उनकी आय में वृद्धि होगी।
- साथ ही, इन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग मजबूत होगी, जिससे निर्यात और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

- विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि केवल आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि झारखंड की आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और शिल्पकला के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
- GI टैग से स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी और आने वाली पीढ़ियों तक इन पारंपरिक कलाओं का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

निष्कर्ष

भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और झारखंड बांस शिल्प को GI टैग मिलना राज्य की सांस्कृतिक और हस्तशिल्प विरासत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह कदम न केवल आदिवासी कारीगरों की आजीविका को सशक्त बनाएगा, बल्कि झारखंड की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

UPSC Prelims MCQs

Q1. Varya AI Model के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- यह भारत का पहला स्वदेशी Distilled Video Story-Generating AI Model है।
- इसे ISRO द्वारा विकसित किया गया है।
- यह Text-to-Video तथा Image-to-Video दोनों प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है।

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

- कथन 1 सही है। Varya भारत का पहला स्वदेशी Distilled Video Story-Generating AI Model है।
- कथन 2 गलत है। इसका विकास Avataar नामक AI कंपनी ने किया है, ISRO ने नहीं।
- कथन 3 सही है। यह Text-to-Video और Image-to-Video दोनों प्रकार के कंटेंट बना सकता है।

UPSC Trap: ISRO, DRDO या MeitY जैसे संस्थानों के नाम देकर भ्रम पैदा किया जा सकता है।

Q2. 'Netra' प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत की पहली स्वदेशी AEW&C प्रणाली है।
2. इसमें AESA रडार लगा है।
3. इसे ISRO ने विकसित किया है।

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

विस्तृत व्याख्या:

- कथन 1 सही है। Netra भारत की पहली स्वदेशी Airborne Early Warning and Control प्रणाली है।
- कथन 2 सही है। इसमें AESA (Active Electronically Scanned Array) Radar का उपयोग किया गया है।
- कथन 3 गलत है। इसका विकास DRDO ने किया है।

UPSC Point: DRDO रक्षा तकनीक विकसित करता है जबकि ISRO अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित है।

Q3. Netra AEW&C प्रणाली का प्रमुख कार्य क्या है?

- (a) उपग्रह प्रक्षेपण
(b) पनडुब्बी निगरानी
(c) हवाई निगरानी एवं कमांड-एंड-कंट्रोल
(d) मिसाइल निर्माण

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

Netra को "Eye in the Sky" कहा जाता है। इसका कार्य हवाई क्षेत्र की निगरानी, दुश्मन विमानों का पता लगाना, लड़ाकू विमानों को दिशा-निर्देश देना और वायु रक्षा संचालन को नियंत्रित करना है।

Q4. H3 Rocket के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह जापान का अगली पीढ़ी का प्लैगशिप लॉन्च व्हीकल है।

- इसे JAXA और Mitsubishi Heavy Industries ने विकसित किया है।
- इसमें LE-9 इंजन का उपयोग किया गया है।

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

विस्तृत व्याख्या:

तीनों कथन सही हैं।

- H3 जापान का अगली पीढ़ी का पल्गशिप रॉकेट है।
- इसे JAXA और Mitsubishi Heavy Industries ने विकसित किया है।
- इसमें आधुनिक LE-9 इंजन लगाया गया है।

UPSC Fact: H3, H-IIA रॉकेट का स्थान लेगा।

Q5. H3 Rocket का उद्देश्य क्या है?

- (a) केवल सैन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण
(b) H-IIA रॉकेट का प्रतिस्थापन
(c) केवल चंद्र अभियानों के लिए उपयोग
(d) केवल वैज्ञानिक प्रयोग

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

H3 को जापान के पुराने H-IIA लॉन्च व्हीकल के स्थान पर विकसित किया गया है। यह वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, सैन्य और भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए उपयोग किया जाएगा।

Q6. AI Data Centers के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- AI डेटा सेंटरों को पारंपरिक डेटा सेंटरों की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है।
- इनका संचालन जल एवं ऊर्जा की अत्यधिक खपत करता है।
- यूरोपीय संघ ने छोटे हरित ऊर्जा आधारित डेटा हब को बढ़ावा देना शुरू किया है।

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

विस्तृत व्याख्या:

- AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए विशाल कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है।
- सर्वरों को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली और पानी की जरूरत होती है।
- यूरोप में बड़े डेटा सेंटरों के स्थान पर छोटे, टिकाऊ और ग्रीन एनर्जी आधारित केंद्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

Q7. AI डेटा सेंटरों के पर्यावरणीय प्रभावों में शामिल हैं:

1. भूजल दोहन
2. ऊर्जा मांग में वृद्धि
3. भूमि क्षरण

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)**विस्तृत व्याख्या:**

डेटा सेंटरों को भारी मात्रा में पानी, भूमि और बिजली की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप भूजल दोहन, ऊर्जा संकट और भूमि उपयोग संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

Q8. India-France ATL Bridge के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह शिक्षा एवं नवाचार सहयोग मंच है।
2. इसमें AIM और La Fondation Dassault Systèmes शामिल हैं।
3. इसका उद्देश्य केवल विश्वविद्यालय स्तरीय अनुसंधान है।

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)**विस्तृत व्याख्या:**

- यह स्कूल स्तर से नवाचार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की पहल है।
- AIM (NITI Aayog) और La Fondation Dassault Systèmes इसके प्रमुख साझेदार हैं।
- इसका फोकस केवल विश्वविद्यालय नहीं बल्कि स्कूली छात्रों पर भी है।

Q9. ATL Bridge में किन तकनीकों पर जोर दिया जाएगा?

1. रोबोटिक्स
2. AI
3. 3D प्रिंटिंग

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)**विस्तृत व्याख्या:**

ATL Labs में Robotics, Artificial Intelligence, 3D Printing, Design Thinking और Microelectronics पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

Q10. BRICS Indore Declaration का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (a) रक्षा सहयोग
- (b) ऊर्जा सुरक्षा
- (c) खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ कृषि
- (d) व्यापार युद्ध

उत्तर: (c)

विस्तृत व्याख्या:

इंदौर घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु-अनुकूल कृषि और कृषि नवाचार को बढ़ावा देना है।

Q11. निम्नलिखित में से कौन-सी पहल BRICS Indore Declaration का हिस्सा है?

1. BRICS Digital Agriculture Network
2. Global Forum on Farmers' Rights in Seed Systems
3. BRICS AgriN

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

विस्तृत व्याख्या:

तीनों पहलें BRICS कृषि सहयोग को मजबूत करने के लिए शुरू की गई हैं।

Q12. BRICS AgriN का संबंध किससे है?

- (a) रक्षा अनुसंधान
- (b) कृषि आदान, आनुवंशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क
- (c) डिजिटल मुद्रा
- (d) अंतरिक्ष अनुसंधान

उत्तर: (b)

विस्तृत व्याख्या:

AgriN का पूरा नाम Agro Inputs, Genetic Resources and Information Network है।

Q13. झारखंड के किन उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ?

1. भगैया सिल्क
2. कुचाई सिल्क
3. मुंडा ज्वेलरी
4. बांस शिल्प

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

विस्तृत व्याख्या:

हाल ही में झारखंड के इन चारों उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है।

Q14. GI टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भौगोलिक उत्पत्ति से जुड़ी पहचान है।
2. इसका संरक्षण GI Act, 1999 के अंतर्गत किया जाता है।
3. GI टैग किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

विस्तृत व्याख्या:

- GI टैग किसी उत्पाद को दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं।
- यह उत्पाद की भौगोलिक पहचान और विशिष्टता को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

Q15. निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए:

1. Varya – AI Video Generation
2. Netra – Airborne Surveillance
3. H3 Rocket – Japan Launch Vehicle
4. ATL Bridge – India-France Innovation Partnership

कितने युग सही सुमेलित हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चार

उत्तर: (d)

विस्तृत व्याख्या:

चारों युग पूर्णतः सही हैं।

- Varya → AI Video Generation
- Netra → Airborne Surveillance
- H3 → Japan Launch Vehicle
- ATL Bridge → India-France Innovation Partnership

UPSC Learning: ऐसे Matching Questions UPSC Prelims में अत्यधिक लोकप्रिय हैं।

UPSC CSE Mains Questions (250 Words)

- Q1. "कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित नवाचार आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान करते हैं, किंतु इनके पर्यावरणीय प्रभाव भी गंभीर चिंताओं को जन्म देते हैं।" Varya AI Model तथा AI Data Centres के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Q2. "आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा में सूचना प्रभुत्व (Information Dominance) और तकनीकी आत्मनिर्भरता पारंपरिक सैन्य शक्ति जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई है।" Netra AEW&C प्रणाली के संदर्भ में भारत की रक्षा तैयारी और आत्मनिर्भरता का मूल्यांकन कीजिए।
- Q3. भारत-फ्रांस ATL Bridge तथा Bharat Innovates 2026 जैसी पहलें शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी कूटनीति के उभरते आयामों को दर्शाती हैं। भारत की वैश्विक नवाचार शक्ति के निर्माण में ऐसी पहलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Q4. "खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और किसानों की आय की चुनौतियाँ परस्पर जुड़ी हुई हैं।" BRICS Indore Declaration के प्रमुख प्रावधानों के आलोक में विकासशील देशों के लिए कृषि सहयोग के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Q5. "स्थानीय ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक सशक्तिकरण के बीच Geographical Indication (GI) एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है।" झारखंड के हाल ही में GI टैग प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में GI प्रणाली की प्रासंगिकता, चुनौतियों तथा संभावनाओं का परीक्षण कीजिए।

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच 2026-27

विषय: इतिहास

To Join Our Courses

Download GS WORLD Learning App

OFFLINE: PRAYAGRAJ | ONLINE: DELHI

STARTING DATE

22 JUNE 2026
8:30 AM

VIJAY VED SIR

9682984000/7905693289

UPPCS PRELIMS
SPECIAL - 2026

विजय संकल्प बैच - 2026

हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के साथ तैयारी

प्रारंभ:
26 जून 2026समय:
रात्रि 8:00 बजेशुल्क:
₹3,999 मात्र

FOR PDF DOWNLOAD GS WORLD LEARNING APP

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच 2026-27

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था

- Daily Revision Test
- साप्ताहिक करेंट मैगजीन
- मेंटर की गाइडेंस
- डाउट क्लीयरिंग सेशंस
- व्यक्तिगत गाइडेंस की सुविधा

कक्षाएँ आरंभ

5 जून सुबह 8:30 बजे

3 दिन की नि:शुल्क
कार्यशाला

JOIN NOW

Visit: www.gsworldias.in | www.courses.gsworldias.in

9682984000/7905693289

RAMESHWAR SIR